The Times of India- 15- May-2023

Irrigation scheme: ₹317 cr sanctioned

Gandhinagar: The state government said on Sunday that it has sanctioned a Rs 317crore project to fill up 74 check dams and lakes in north Gujarat with water from the Dharoi dam.

An official statement said the project will involve laying 118 kilometre long pipelines from the Dharoi dam to reservoirs in two talukas of Satlasana and Kheralu. A total of 5,808 hectares of cultivable land will receive water through the project, benefiting more than 2,700 farmers, the release added.

37 villages of these two talukas have remained out of the Dharoi dam command area because of the geographical conditions prevalent there, the statement said. With farmers relying on ground water for their crops, the water table has been depleting in these villages.

Representations in this regard have been made to the state government from various quarters. TNN

The Telegraph- 15- May-2023

A seminar on the erosion in progress in Malda on Sunday. (Soumya De Sarkar)

Central panel for solution to erosion

SOUMYA DE SARKAR

Malda: The Narendra Modi government at the Centre has constituted a high-power committee to find out a permanent solution to the Ganga's erosion in Malda and Murshidabad districts, said a senior official of the Farakka Barrage Project Authority here on Sunday.

"A committee was recently constituted by the Centre to explore solutions to the Ganga's erosion. River experts, representatives of the central river commission and the Union water resource ministry, the chief engineer of the state irrigation department and officials of the barrage authority have been included in it," R.D. Deshpande, the general manager of the FBPA, said.

He was here to attend a seminar organised by the Ganga Bhangan Pratirodh Action Committee (GBPAC) and the Jana Andolan, a Calcutta-based social organisation, at Town Hall.

In Malda and Murshidabad, Ganga has been gobbling land, houses and other properties for years. Hundreds of people have become homeless because of the erosion on either bank of the river.

Chief minister Mamata Banerjee had recently accused the Centre of not doing enough to stem the erosion.

At Sunday's seminar, around 500 erosion victims were present. Those representing the social organisations have said as the Ganga is the national river, the Centre must shoulder the responsibility of taking up the anti-erosion work.

Amar Ujala- 15- May-2023

प्रदेश में सूख गईं 23% झीलें और छोटे-बड़े तालाब

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने पहली बार जारी की वाटर बॉडीज सेंसस रिपोर्ट

विनोद मुसान

देहरादून। उत्तराखंड में मौजूद 3096 जलाशयों (झील, झाल, छोटे-बड़े तालाब, टैंक) में से 725 (23.4%) पूरी तरह से सूख गए हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से देशभर में पहली बार कराए गए सर्वे के बाद वाटर बॉडीज सेंसस (जलस्रोत गणना) रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

प्रदेश में कुल 3096 जलाशय हैं। इनमें से 2970 ग्रामीण क्षेत्रों (95.9 प्रतिशत) और 126 (4.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में हैं। इसमें से 2371 जलाशयों (76.6 प्रतिशत) में ही पानी पाया गया है, जबकि 725 जलाशय (23.4 प्रतिशत) पूरी तरह से सूख चुके हैं। रिपोर्ट में जलाशयों के सूखने का कारण जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी, गाद भरने और स्रोतों के सिमटने को बताया गया है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं, जिन्हें पुनर्जीवित भी नहीं किया जा सकता है। कई जलाशयों में अतिक्रमण हो चुका है।

3096 कुल जलाशय हैं प्रदेश में

725 जलाशय सूख गए

फैक्ट फाइल

1654 प्राकृतिक जलाशय हैं
इनमें से 1560 ग्रामीण इलाकों में हैं और 94 शहरी इलाकों में हैं

1442 मानव निर्मित जलाशय हैं
इनमें में 1410 ग्रामीण इलाकों में हैं और 32 शहरी इलाकों में है।

पुरानों की सुध नहीं, नए बनाने पर जोर

प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के तहत देशभर नए जलाशय बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी इस योजना के तहत अब तक 1133 जलाशयों का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन वर्षों पुराने जलाशय दम तोड़ रहे हैं। कभी ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रहे ये जलाशय अब सरकार और स्थानीय लोगों की उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। जलाशयों के सूखने की जो तस्वीर रिपोर्ट में सामने आई है, भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए हिसाब से वह सही नहीं है।

2361 जलाशय सरकारी संपत्ति में दर्ज हैं।

735 जलाशय निजी संपत्ति में दर्ज हैं।

कहां कितने स्रोत सूखे

उत्तर प्रदेश	2,45,087
झारखंड	1,07,508
बिहार	45,793
हरियाणा	14,898
दिल्ली	893

ये एक गंभीर समस्या है। प्रदेश में प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के तहत नए जलाशयों का निर्माण के साथ पुराने जलाशयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1133 अमृत सरोहर का निर्माण किया जा चुका है। आने वाले दिनों में तस्वीर बदलेगी। – **आनंद स्वरूप**, निदेशक पंचायती राज एवं आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग

एक जलाशय का फायदा एक या उससे अधिक कस्बों को

प्रदेश में जो जलाशय इस्तेमाल में हैं, उनमें से 83.2 प्रतिशत यानी 1973 में से किसी एक शहर या कस्बे को फायदा होता है, जबकि 16.2 प्रतिशत यानी 383 जलाशयों से दो से पांच शहरों या कस्बों को पानी मिलता है। शेष 0.6 प्रतिशत यानी 15 जलाशयों से पांच से ज्यादा शहरों या कस्बों को पानी मिलता है। कुल 3096 जलाशयों में से 82.9% यानी 2,567 जलाशय 0.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में हैं, जबकि स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कुल जलाशयों में 41.5 प्रतिशत 1286 की क्षमता एक हजार से दस हजार घनमीटर के बीच है।

Rajasthan Patrika- 15- May-2023

धरोई बांध के पानी से भरे जाएंगे उत्तर गुजरात के 74 तालाब और चेकडैम

किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का अहम निर्णय

राजस्थान पत्रिका
NewSmile
न्यूज विद स्माइल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

गांधीनगर. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने उत्तर गुजरात की दो तहसील सतलासणा और खेरालू के 53 गांवों के तालाब और चेकडेम समेत 74 तालाबों, चेकडेम साबरमती जलाशय (धरोई बांध) योजना के पानी से भरने का किसानों के हित में अहम निर्णय किया है। मेहसाणा जिले की सतलासणा तहसील के धरोई बांध में साबरमती नदी पर निर्मित धरोई बांध के कमाण्ड एरिया की भौगोलिक स्थित के मुताबिक दो तहसीलों के 37 गांवों को कमाण्ड एरिया में शामिल नहीं किया जा सका। इन तहसीलों के किसान मुख्यतः पशुपालन और कृषि आधारित रोजगार करते हैं। इन क्षेत्रों में बारिश की अनियमितता के कारण भूगर्भ जलस्तर भी गहराई में चला गया है। यही नहीं सिंचाई और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के समक्ष इस समस्या के निवारण के लिए यहां के किसान और नेताओं ने पेशकश की थी, जिस पर सकारात्मक निर्णय किया गया है।

बिछाई जाएगी नई पाइप लाइन

मुख्यमंत्री के निर्णय के मुताबिक धरोई बांध का पानी इन दोनों तहसीलों-सतलासणा और खेरालू के गांवों में उपयोग हो सके इसके लिए नई पाइप लाइन बिछाकर खेरालू और सतलासण के तालाबों को भरा जाएगा। इसके जरिए भूगर्भ जलस्तर ऊपर लाने का आयोजन है। इन दोनों तहसीलों के 53 गांवों के तालाब और चेकडैम को सीधा जोड़ने और आठ तालाबों व 5 चेकडैम को परोक्ष तरीके से जोड़कर कुल 74 तालाबों और चेकडैम से 5808 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए 118.14 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाई जाएगी। दो तहसीलों के 2700 से ज्यादा किसानों को सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार 317 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन तालाबों को धरोई बांध से चरणबद्ध तरीके से भरने के लिए 400 मिलियन घनफीट पानी लिया जाएगा।